3 स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति- साय

5 कुशल और कूटनीतिक विदेश मंत्री हैं जयशंकर

6 आज अगर बाबासाहब अम्बेडकर होते

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 49 प्रति सोमवार, 13 अप्रैल 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

सत्ता के काले खेल की जद में आया धान का कटोरा 'छत्तीसगढ़'

सत्ता के संरक्षण में धान का खेल, अन्नदाताओं के साथ हुआ धोखा

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यह पहचान केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि यहां के लाखों किसानों की मेहनत, पसीने और उम्मीदों का प्रतीक है। लेकिन जब इसी धरती पर किसानों की मेहनत से उपजे धान के साथ कथित तौर पर बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आता है, तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि विश्वासघात बन जाता है। हालिया आरोपों के अनुसार खाद्य मंत्री दयालदास बघेल और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गहरी चोट करते हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों नहीं, बल्कि लाखों क्विंटल धान गायब हो गई है। बेमेतरा के सरदा संग्रहण केंद्र से 53,639 क्विंटल धान का गायब होना कोई मामूली गड़बड़ी नहीं हो सकती। सूरजपुर में 7000 क्विंटल धान का कोई हिसाब नहीं है। कवर्धा के बतार चारभाटा केंद्र में 06 लाख

46 हजार क्विंटल धान की कमी पाई गई। यह आंकड़ा किसी भी सामान्य प्रशासनिक त्रुटि से कहीं आगे जाता है। महासमुंद के तीन केंद्रों में 18 करोड़ रुपये के धान का गायब होना इस घोटाले को और भी गंभीर बनाता है। सवाल यह उठता है कि क्या यह सब केवल लापरवाही है, या फिर एक सुनियोजित तंत्र के तहत किया गया आर्थिक अपराध? क्योंकि अगर सरकार छोटे कर्मचारियों पर धान घोटाले का आरोप मथ रही है तो यह सही नहीं है, क्योंकि बगैर वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के संरक्षण के छोटे कर्मचारी धान का एक दाना भी इधर से उधर नहीं कर सकते हैं।

पूर्व में भी विवादों में घिरे रहे हैं केदार कश्यप और बघेल

छत्तीसगढ़ की राजनीति में केदार कश्यप और दयालदास बघेल कोई नए नाम नहीं हैं, लेकिन समय-समय पर इन पर लगे आरोपों ने उनकी छवि को विवादों से अलग नहीं होने दिया। सहकारिता और वन जैसे अहम विभागों से जुड़े रहने के दौरान केदार कश्यप पर पहले भी प्रशासनिक निर्णयों में पक्षपात और संसाधनों के प्रबंधन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दलों ने कई बार आरोप लगाया कि विभागीय कामकाज में पारदर्शिता की कमी रही और स्थानीय स्तर पर शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसी तरह खाद्य विभाग से जुड़े दयालदास बघेल पर भी अतीत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न प्रबंधन को लेकर अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं। (शेष पेज 2 पर)

वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ का उभरता आदर्श मॉडल

-विजया पाठक

भारतीय समाज की संरचना में बुजुर्गों का स्थान सदैव सर्वोच्च रहा है। वे केवल परिवार के मुखिया या आश्रयदाता ही नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा, अनुभव और मूल्यों के जीवंत स्रोत होते हैं। बदलते समय के साथ जब पारिवारिक ढांचे छोटे हो रहे हैं और सामाजिक रिश्तों में औपचारिकता बढ़ती जा रही है, तब वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सम्मानजनक, सुरक्षित और सक्रिय बनाए रखना शासन की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इसी चुनौती को अवसर में बदलते हुए छत्तीसगढ़ ने एक ऐसा मॉडल विकसित किया है, जो देशभर में उदाहरण के रूप में उभर रहा है। इस मॉडल के केंद्र में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की वह सोच है, जिसमें बुजुर्गों को समाज की आत्मा माना गया है। उनका स्पष्ट मानना है कि माता-पिता और बुजुर्गों का सम्मान ही सच्चे अर्थों में समाज की प्रगति का आधार है। इसी सोच को नीतियों और योजनाओं के माध्यम से जमीनी स्तर तक उतारने का कार्य राज्य सरकार ने प्रभावी रूप से किया है।

सर्विस सेंटर की स्थापना एक अभिनव पहल

राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए केवल योजनाएं बनाकर छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें व्यवस्थित ढंग से लागू भी किया गया है। वृद्धाश्रमों की संख्या और गुणवत्ता दोनों में सुधार इसका प्रमाण है। वर्तमान में राज्य में 35 वृद्धाश्रम संचालित हो रहे हैं, जहां हजार से अधिक बुजुर्गों को आवास, भोजन, स्वास्थ्य सुविधा और मानसिक परामर्श जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह केवल आश्रय देने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देने का प्रयास है। (शेष पेज 3 पर)

अन्नदाता के साथ अन्याय का आरोप, कटघरे में बैरसिया विधायक विष्णु खत्री

सत्ता, सौदे और सवालः जांच की मांग तेज

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों बैरसिया क्षेत्र के विधायक विष्णु खत्री को लेकर उठे आरोप चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनमें कथित रूप से वेयरहाउस में बड़ी मात्रा में गेहूं का मामला, जमीन खरीद में अनियमितता और किसानों से कम दाम पर उपज लेने जैसे आरोप शामिल हैं। यह प्रकरण केवल एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इससे प्रदेश की कृषि व्यवस्था, राजनीतिक जवाबदेही और किसान-सरकार संबंधों पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार बैरसिया क्षेत्र के एक वेयरहाउस में करीब 500 टन गेहूं पाया गया, जिसे लेकर यह आरोप सामने आया कि यह अनाज किसानों से जबरन कम कीमत पर खरीदा गया था। (शेष पेज 2 पर)

अन्नदाता के साथ अन्याय का आरोप, कटघरे में बैरसिया विधायक विष्णु खत्री

(पेज 1 का शेष)

यदि यह आरोप तथ्यात्मक रूप से सही सिद्ध होते हैं, तो यह सीधे-सीधे किसानों के अधिकारों का हनन माना जाएगा। किसान अपनी मेहनत से फसल उगाते हैं और यदि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता, तो यह उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि सरकार लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों को सुरक्षा देने की बात करती है। ऐसे में यदि स्थानीय स्तर पर ही किसानों से कम दाम में उपज ली जा रही है, तो यह व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है।

जमीन खरीद में अनियमितताओं के आरोप

मामले का दूसरा पहलू जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि विधायक द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए किसानों से औने-पौने दाम पर जमीन खरीदी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जानकारी और संसाधनों की कमी के कारण किसान उचित सौदे नहीं कर पाते, ऐसे में यदि प्रभावशाली लोग इसका लाभ उठाते हैं, तो यह नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से गंभीर विषय बन जाता है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि के लिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है, लेकिन इस तरह की खबरें सामने आना ही बताता है कि कहीं न कहीं पारदर्शिता की कमी महसूस की जा रही है।

किसानों का बढ़ता असंतोष

इन घटनाओं के बाद किसान संगठनों में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। सूत्रों के अनुसार किसान संगठन इस पूरे मामले की शिकायत देश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की तैयारी में हैं। विशेष रूप से नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान से इस विषय में हस्तक्षेप की मांग की जा सकती है। किसानों का कहना है कि यदि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उनका यह भी मानना है कि यदि समय रहते इस तरह के मामलों पर सख्ती नहीं की गई, तो भविष्य में ऐसे प्रकरण और बढ़ सकते हैं।

संगठन की चुप्पी पर सवाल

इस पूरे मामले में राजनीतिक संगठन की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आरोप है कि पार्टी स्तर पर इस मामले को लेकर कोई स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है, जिससे यह धारणा बन रही है कि कहीं न कहीं मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। हालांकि, किसी भी संगठन के लिए यह जरूरी होता है कि वह अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर नजर रखे और यदि कोई आरोप सामने आता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे। यह पूरा प्रकरण कई स्तरों पर गंभीर है किसानों के आर्थिक हित, राजनीतिक नैतिकता और प्रशासनिक पारदर्शिता। ऐसे में सबसे जरूरी है कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि यह संदेश जाए कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं यदि आरोप निराधार साबित होते हैं, तो यह भी जरूरी है कि सच्चाई सामने आए, ताकि अनावश्यक भ्रम दूर हो सके। यह मामला केवल बैरसिया या एक विधायक तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक व्यवस्था की ओर संकेत करता है, जिसमें किसानों और बाजार के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर ही होता है। यदि वहीं पर गड़बड़ी होती है, तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।किसानों की मेहनत और उनके अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव होते हैं। ऐसे में यदि कहीं भी उनके साथ अन्याय की आशंका होती है, तो उसे गंभीरता से लेना आवश्यक है। बैरसिया का यह मामला भी उसी दिशा में एक संकेत है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को और मजबूत करने की जरूरत है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या वास्तव में किसानों को न्याय मिल पाता है। क्योंकि अंततः यही तय करेगा कि व्यवस्था कितनी मजबूत और भरोसेमंद है।

सत्ता के संरक्षण में धान का खेल, अन्नदाताओं के साथ हुआ धोखा

(पेज 1 का शेष)

राशन वितरण में गड़बड़ी, भंडारण व्यवस्था की कमजोरी और निगरानी तंत्र की ढिलाई जैसे मुद्दे बार-बार उठते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जब किसी मंत्री के कार्यकाल में बार-बार एक जैसे आरोप सामने आते हैं, तो यह केवल संयोग नहीं माना जा सकता। यह प्रशासनिक प्रणाली में गहराई तक जमी समस्याओं या नेतृत्व की शैली पर सवाल खड़े करता है।

धान को चूहों द्वारा खा जाना हास्यास्पद

सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि अधिकारियों द्वारा दिए गए तर्क धान को चूहे खा गए हैं। इस पूरे मामले को हास्यास्पद और गंभीर दोनों बना दिया है। क्या लाखों क्विंटल धान चूहे खा सकते हैं? क्या यह जवाब जनता और किसानों के साथ मजाक नहीं है? यह तर्क केवल प्रशासनिक अक्षमता को नहीं, बल्कि संभावित भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास भी प्रतीत होता है। जब जिम्मेदार अधिकारी ऐसे तर्क देते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि कहीं न कहीं सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है।

दलालों का खेल और किसानों की दुर्दशा

एक और महत्वपूर्ण पहलू है अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में धान की कीमतों में अंतर है। जहां ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना में धान का मूल्य लगभग 1900 रुपये प्रति क्विंटल बताया जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में यह 3100 रुपये तक पहुंच गया। इस कारण से ही इन राज्यों के सक्रिय दलाल छत्तीसगढ़ में धान बेचते हैं। और मुनाफा कमाते हैं। इस गोरखधंधे के पीछे दलालों की सक्रियता और सरकारी तंत्र की मिलीभगत है। दलालों के इस खेल में असली नुकसान छत्तीसगढ़ के किसान का ही होता है।

प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप

इस पूरे प्रकरण में केवल मंत्री ही नहीं, बल्कि कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में बताई जा रही है। सहकारिता सचिव सी.आर. प्रसन्ना और कृषि सचिव शहला निगार के नाम भी चर्चाओं में हैं। अगर यह आरोप सही है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि घोटाला केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि ऊपरी स्तर तक फैला हुआ हो सकता है। इसके अलावा, धान का वजन बढ़ाने के लिए पाइप से पानी डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। इस गोरखधंधे में लिप्त कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह केवल भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सीधे-सीधे किसानों और सरकारी संसाधनों के साथ धोखाधड़ी है।

भाजपा सरकार की छवि पर सवाल

राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा खुद को किसानों का हितैषी और अन्नदाता का संरक्षक बताती रही है। लेकिन इस कथित घोटाले ने उस छवि पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर सरकार सच में किसानों के हित में काम कर रही है, तो इतने बड़े स्तर पर अनियमितताएं कैसे हो गईं? क्या यह प्रशासनिक विफलता है या फिर सत्ता के संरक्षण में पनप रहा भ्रष्टाचार?

लाखों किसान हुए इस घोटाले से प्रभावित

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित किसान ही हैं। वे, जिनकी मेहनत से यह धान पैदा होता है, आज अपने ही हक के लिए भटक रहे हैं। भुगतान में देरी, फसल की चोरी और सरकारी तंत्र की उदासीनता ने उन्हें निराश कर दिया है। इतने गंभीर आरोपों के बाद सबसे बड़ा सवाल है जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या केवल कुछ कर्मचारियों को निलंबित कर देने से मामला खत्म हो जाएगा? या फिर उच्च स्तर पर भी जांच और कार्रवाई होगी? जरूरत है एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की, जिसमें हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए। अगर मंत्री स्तर तक की भूमिका संदिग्ध है, तो जांच वहीं तक पहुंचनी चाहिए।

विश्वास की बहाली ही सबसे बड़ी चुनौती

छत्तीसगढ़ का यह कथित धान घोटाला केवल आर्थिक नुकसान का मामला नहीं है, बल्कि यह जनता और सरकार के बीच विश्वास के टूटने का भी संकेत है। जब किसानों को ही अपने उत्पाद की सुरक्षा और उचित मूल्य पर भरोसा न रहे, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। अब समय है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और किसानों का विश्वास फिर से जीतने की कोशिश करे। क्योंकि अगर धान का कटोरा ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तो यह केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय होगा।

बच्चों के अधिकारों से संबंधित कानूनी मुद्दे

-डॉ. विजय गर्ग

बच्चे समाज के सबसे कमजोर सदस्य हैं और उनकी सुरक्षा, विकास और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कानून और अंतर्राष्ट्रीय समझौते बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक रूपरेखाओं में से एक है बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जो यह मान्यता देता है कि प्रत्येक बच्चे को जीवित रहने, सुरक्षा, विकास और भागीदारी का अधिकार है। ऐसे कानूनी ढांचे के बावजूद, भारत सहित कई देशों में बच्चों के अधिकारों से संबंधित कई कानूनी मुद्दे मौजूद हैं।

प्रमुख कानूनी चिंताओं में से एक बाल श्रम है। यद्यपि कानून खतरनाक उद्योगों में बच्चों को रोजगार देने से रोकते हैं, फिर भी कई बच्चे कारखानों, खेतों, घरेलू कार्यों और छोटे व्यवसायों में काम करते हैं। गरीबी, शिक्षा की कमी और कानूनों का कमजोर प्रवर्तन इस समस्या में योगदान देता है। भारत में बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम का उद्देश्य बच्चों के शोषण को रोकना है, फिर भी ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों में इसका कार्यान्वयन एक चुनौती बनी हुई है।

एक अन्य गंभीर मुद्दा बाल दुर्व्यवहार और शोषण है। बच्चे घर, स्कूल या कार्यस्थल पर शारीरिक, भावनात्मक या यौन दुर्व्यवहार का शिकार हो सकते हैं। इससे निपटने के लिए, भारत ने यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम लागू किया, जिसे आमतौर पर POCSO के नाम से जाना जाता है। यह कानून बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए सख्त सजा प्रदान करता है और त्वरित परीक्षण के लिए विशेष अदालतें स्थापित करता है। हालांकि, सामाजिक कलंक, जागरूकता की कमी और कानूनी प्रक्रियाओं में देरी अक्सर पीड़ितों को समय पर न्याय प्राप्त करने से रोकती है।

बाल विवाह एक और गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद, परंपरा, गरीबी और लैंगिक भेदभाव के कारण कुछ समुदायों में शीघ्र विवाह जारी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम में लड़कियों के लिए कानूनी विवाह की आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है तथा बाल विवाह में शामिल लोगों को दंडित किया गया है। फिर भी दूरदराज के क्षेत्रों में प्रवर्तन कठिन है, जहां सामाजिक रीति-रिवाज कभी-कभी कानूनी मानदंडों को ओवरराइड कर देते हैं।

शिक्षा का अधिकार बच्चों के अधिकारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा बच्चों को सशक्त बनाती है और उन्हें शोषण और गरीबी से बचाती है। भारत में, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बच्चों का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। फिर भी, कई बच्चे आर्थिक कठिनाइयों, पारिवारिक जिम्मेदारियों या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की कमी के कारण स्कूल छोड़ देते हैं।

कानून के विरुद्ध संघर्ष करने वाले बच्चों को भी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किशोर न्याय प्रणाली का उद्देश्य युवा अपराधियों को दंडित करने के बजाय सुधार करना है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम उन बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास का प्रावधान करता है जो जरूरतमंद हैं या कानून के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हालाँकि, भीड़भाड़ वाली संस्थाएं, अपर्याप्त पुनर्वास कार्यक्रम और प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी अक्सर इसकी प्रभावशीलता में बाधा डालती है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना न केवल कानूनी जिम्मेदारी है बल्कि समाज का नैतिक दायित्व भी है। मजबूत कानून मौजूद हैं, लेकिन उनकी सफलता उचित प्रवर्तन, सार्वजनिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी पर निर्भर करती है।

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश में पांच नए मेडिकल कॉलेज, 14 नर्सिंग कॉलेज तथा एक होम्योपैथी कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला हैं और इसी दृष्टिकोण के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और गुणवत्ता सुधार पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। पहली बार आयोजित इस एक दिवसीय सम्मेलन के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में नवाचारों का व्यापक आदान-प्रदान होगा, जो आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस मंच से निकले विचार

न केवल नीति निर्माण को दिशा देंगे, बल्कि आमजन तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में भी सहायक होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलना उनके लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को कर्ज लेने या जमीन बेचने जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह स्थिति तेजी से बदल रही है और स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास बढ़ा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियां, जो पहले सीमित वर्ग तक मानी जाती थीं, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रही हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा "आरोग्य मंदिर" जैसी पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा देश में तीन आयुर्वेदिक एम्स स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री साय ने चिकित्सकों को समाज में भगवान के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान बताते हुए उनसे सेवा भाव के साथ संवेदनशीलता बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सम्मेलन स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मार्ग प्रशस्त करेगा और इसके सकारात्मक परिणाम आम जनता तक पहुंचेंगे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि नक्सल समस्या के समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर होगा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन से प्राप्त सुझाव आयुष मंत्रालय को भेजे जाएंगे और यह आयोजन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में प्रेरक भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की जनगणना 2027 अभियान की शुरुआत

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि "जनगणना 2027 देश के विकास की आधारशिला है। डिजिटल माध्यम से की जा रही यह जनगणना पारदर्शिता और सटीकता को सुनिश्चित करेगी। मैं प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे स्वयं आगे आकर स्व-गणना करें और इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनें।" मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी नागरिक स्व-गणना पोर्टल का उपयोग कर अपने परिवार की सही और पूर्ण जानकारी दर्ज करें। उन्होंने कहा कि यह न केवल आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, बल्कि भविष्य की योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में भी सहायक होगा।

मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 के अंतर्गत अपनी स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी करते हुए राज्य में इस महत्वपूर्ण अभियान की औपचारिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना की ओर अग्रसर हुआ है, जो पारदर्शिता, सटीकता और जनभागीदारी को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत को डिजिटल युग में एक और मजबूत कदम आगे बढ़ाने वाली है। जनगणना 2027 का पहला चरण 'हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना' है, जिसके अंतर्गत आवासीय स्थिति, सुविधाओं और घरेलू विवरणों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की जा रही है। इस बार 'स्व-गणना' की सुविधा के माध्यम से नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और त्रुटिरहित होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों से जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से संपन्न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह डेटा राज्य और देश की नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए इसकी शुद्धता अत्यंत आवश्यक है।

ऑनलाइन आईपीएल सट्टा पर प्रभावी कारवाही, 02 अपराध दर्ज, बुकियों का होगा जल्द खुलासा

- नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन एवं अनुविभागीय अधिकारी SDOP जितेंद्र पाठक के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस ऑनलाइन सट्टा पकड़ने मे सफलता प्राप्त की है। संभवतः जिला मुख्यालय पर पहला आईपीएल का यह मामला होगा जब पुलिस ने अपने तकनीकी ज्ञान के साथ आरोपियों तक पहुंची है। ज्ञात हो कि वर्तमान मे आईपीएल क्रिकेट लीग चल रही है और आईपीएल मैच से पिछले वर्षों में कई युवाओ को उनके परिवार ने खोया है तथा युवा वर्ग आईपीएल मैच के सट्टा से पीड़ित होकर लगातार कर्ज के बोझो के तले दबा जा रहा है। इन्ही सब कारणों से पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस थोटा द्वारा आईपीएल सट्टा पर लगातार कार्यवाही किये जाने हेतु जिले के समस्त प्रभारियो को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के पालन में थाना कोतवाली नर्मदापुरम द्वारा 3अप्रैल को मुखबिर की सूचना पर आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स v/s पंजाब किंग्स एलेव्न के मैच पर सट्टा खिलाते आरोपी शेख अफजल पिता शेख फिरोज अमर चौक हाल मुकाम कालिका नगर नर्मदापुरम को उसके एक साथी नाहिद पिता आबिद खान निवासी अमर चौक नर्मदापुरम को 3अप्रैल की रात्री मैच के दौरान मोबाइल पर लोगो से सट्टा लिखाते हुये रंगे हाथों पकड़कर शेख अफजल के कब्जे से 01 android मोबाइल, 01 keyped मोबाइल एवं सट्टे के हिसाब लिखे 02 पेज, 01 लीड पेन एवं नगद 7,500/- तथा आरोपी नाहिद खान से 01 keyped मोबाइल विधिवत जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध सट्टा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी थी।

वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ का उभरता आदर्श मॉडल

(पेज 1 का शेष)

इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल पीपीपी मॉडल के तहत आधुनिक वृद्धाश्रमों की स्थापना है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग जैसे प्रमुख शहरों में इन सुविधाओं का विस्तार यह दर्शाता है कि सरकार बुजुर्गों के लिए आधुनिक और गरिमापूर्ण जीवनशैली सुनिश्चित करने को लेकर गंभीर है। इसके साथ ही असहाय और दिव्यांग बुजुर्गों के लिए उपकरण सर्विस सेंटर की स्थापना एक अभिनव पहल है, जो उनकी दैनिक जरूरतों को सरल बनाती है।

सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए "सियान गुड़ी" जैसे केंद्रों का विस्तार भी एक सराहनीय कदम है। ये केंद्र केवल मिलने-जुलने के स्थान नहीं हैं, बल्कि यहां बुजुर्गों को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों से जोड़कर उन्हें सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखा जाता है। इससे उनमें अकेलेपन की भावना कम होती है और जीवन के प्रति उत्साह बना रहता है। राज्य की समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में इन योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका यह दृष्टिकोण कि "संवेदनशील शासन का अर्थ है हर बुजुर्ग तक सेवा और सुरक्षा पहुंचाना", इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

नियमित चिकित्सा, देखभाल उपलब्ध

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ ने उल्लेखनीय कार्य किया है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए छह जिलों में प्रशामक देखभाल गृह संचालित किए जा रहे हैं, जहां निःशुल्क इलाज, दवाइयां और नियमित चिकित्सा देखभाल उपलब्ध है। इसके अलावा आयुष्मान भारत और शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत लाखों वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त उपचार की सुविधा दी गई है। यह पहल न केवल आर्थिक बोझ कम करती है, बल्कि बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी सुनिश्चित करती है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए सख्ती से पालन किया जा रहा है। अनुविभागीय और जिला स्तर पर बनाए गए अधिकरणों के माध्यम से बुजुर्गों को त्वरित न्याय मिल रहा है। इससे उनकी संपत्ति, भरण-पोषण और सुरक्षा से जुड़े मामलों का समाधान प्रभावी तरीके से हो पा रहा है। आर्थिक सुरक्षा भी बुजुर्गों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

पेंशन योजना का मिल रहा लाभ

राज्य सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 60 से 79 वर्ष के बुजुर्गों को मासिक सहायता और 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ी हुई राशि प्रदान की जा रही है। 14 लाख से अधिक बुजुर्गों का इस योजना से जुड़ना इसकी व्यापकता और प्रभाव को दर्शाता है। इसके अलावा सहायक उपकरण प्रदाय योजना के अंतर्गत हजारों बुजुर्गों को व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, छड़ी और चश्मे जैसे उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। ये छोटे-छोटे प्रयास उनके जीवन को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन के लिए राज्य सरकार ने तीर्थयात्रा योजनाओं को भी प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना और रामलला दर्शन योजना के माध्यम से लाखों बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर मिला है। यात्रा के दौरान भोजन, आवास और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि वे बिना किसी चिंता के इस अनुभव का आनंद ले सकें। हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को बढ़ावा मिलता है। यह केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं।

योजनाओं का समूह नहीं

समग्र रूप से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का यह मॉडल केवल योजनाओं का समूह नहीं है, बल्कि एक समावेशी और संवेदनशील दृष्टिकोण का परिणाम है। यहां बुजुर्गों को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि समाज के सम्मानित सदस्य के रूप में देखा जाता है। आज जब कई राज्यों में बुजुर्गों की समस्याएं गंभीर रूप ले रही हैं, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ ने यह साबित किया है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति और संवेदनशील प्रशासन साथ हो, तो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। यह मॉडल न केवल राज्य के भीतर सामाजिक समरसता को मजबूत कर रहा है, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है जहां बुजुर्गों का सम्मान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि नीतियों और कार्यों में भी दिखाई देता है।

सम्पादकीय

कितनी सफल होगी ईरान और अमेरिका के बीच समझौता वार्ता

ईरान और अमेरिका के बीच समझौता वार्ता एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। यह वार्ता मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है, जिसे लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ है। 2015 में हुए समझौते को इस दिशा में एक बड़ी सफलता माना गया था, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के इस समझौते से हटने के बाद स्थिति फिर से जटिल हो गई। अब जब दोनों देश एक बार फिर बातचीत की मेज पर हैं, तो सवाल उठता है कि क्या यह वार्ता सफल हो पाएगी? इस वार्ता की सफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला मुद्दा विश्वास का है। अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से अविश्वास की गहरी खाई रही है। ईरान का मानना है कि अमेरिका ने पहले समझौते को तोड़कर उसकी विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाई, जबकि अमेरिका को ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता पर संदेह है। ऐसे में विश्वास बहाली इस वार्ता की सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्रीय राजनीति है। मध्य पूर्व में ईरान की भूमिका हमेशा से विवादित रही है। इजराइल और सऊदी अरेबिया जैसे देश ईरान के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं। ये देश नहीं चाहते कि ईरान को ऐसी कोई छूट मिले जिससे उसकी सैन्य या रणनीतिक ताकत बढ़े। इसलिए अमेरिका पर भी इन देशों का दबाव बना रहता है, जो वार्ता को जटिल बनाता है।

तीसरा पहलू घरेलू राजनीति का है। अमेरिका में किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते को लेकर राजनीतिक मतभेद होते हैं। जो बाइडेन की सरकार वार्ता को आगे बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन आंतरिक विरोध इसे सीमित कर सकता है। इसी तरह ईरान में भी कठोर रुख अपनाने वाले नेताओं का प्रभाव है, जो अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद वार्ता के सफल होने की संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। दोनों देशों के पास इस समझौते को आगे बढ़ाने के ठोस कारण हैं। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध उसकी अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में वह प्रतिबंधों से राहत चाहता है। वहीं अमेरिका भी मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखना चाहता है और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना उसकी प्राथमिकता है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर भी इस समझौते की सफलता महत्वपूर्ण है। यदि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होता है, तो यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की एक बड़ी उपलब्धि होगी और अन्य विवादों को सुलझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इससे ऊर्जा बाजार में स्थिरता आएगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। फिर भी, यह कहना मुश्किल है कि यह वार्ता पूरी तरह सफल होगी। अधिक संभावना यही है कि दोनों पक्ष किसी "मध्यम मार्ग" पर सहमत हों, जिसमें आंशिक प्रतिबंध हटाने और सीमित परमाणु नियंत्रण जैसे उपाय शामिल हों। पूर्ण और स्थायी समाधान के लिए दोनों देशों को अपने पुराने मतभेदों से ऊपर उठकर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

ईरान और अमेरिका के बीच समझौता वार्ता की सफलता न केवल इन दो देशों के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह वार्ता कूटनीति की परीक्षा है, जिसमें धैर्य, विश्वास और समझदारी की आवश्यकता है। यदि दोनों पक्ष इन मूल्यों को अपनाते हैं, तो यह संभव है कि लंबे समय से चला आ रहा यह विवाद किसी समाधान की ओर बढ़ सके।

सियासी गहमागहमी

निगम मंडल की कुर्सी के चक्कर में सपनों में उलझे हैं नेतागण

मध्यप्रदेश में भाजपा नेताओं के लिए निगम-मंडलों की कुर्सियां लंबे समय से राजनीतिक संतुलन और संगठनात्मक संतुष्टि का साधन रही हैं, लेकिन इस बार कई नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। सत्ता में सक्रिय भूमिका की अपेक्षा रखने वाले अनेक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता इस इंतजार में थे कि उन्हें किसी न किसी निगम या मंडल में जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे उनकी राजनीतिक सक्रियता और प्रभाव बना रहे। परंतु नियुक्तियों में हो रही देरी और सीमित पदों के कारण असंतोष की स्थिति बनती दिख रही है। भाजपा के भीतर यह एक चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि संगठन को संतुलित रखते हुए सभी वर्गों और नेताओं को साधना आसान नहीं होता। खासकर उन नेताओं के लिए, जिन्होंने चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाई, यह स्थिति निराशाजनक हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी नेतृत्व फिलहाल संतुलन और रणनीति के आधार पर फैसले लेना चाहता है, ताकि भविष्य के चुनावों में कोई आंतरिक मतभेद उभरकर सामने न आए। हालांकि, लंबे समय तक उपेक्षा की भावना बनी रही तो यह असंतोष संगठन के लिए चुनौती बन सकता है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस में नहीं दिख रही नेताओं में एकजुटता

मध्यप्रदेश कांग्रेस में इन दिनों जिस तरह की अंदरूनी खींचतान सामने आ रही है, उसने संगठन की एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में पार्टी को नए सिरे से संगठित करने की कोशिशें जरूर हुईं, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम नजर नहीं आ रहे। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है। चुनावी हार के बाद आत्ममंथन और पुनर्गठन की जरूरत थी, लेकिन आपसी मतभेदों ने इस प्रक्रिया को कमजोर कर दिया। यही कारण है कि कांग्रेस प्रदेश में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में भी पूरी तरह सफल नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जीतू पटवारी का संगठन को आक्रामक और सक्रिय बनाने का प्लान कागजों तक सीमित रह गया है। स्थानीय स्तर पर गुटबाजी, नेतृत्व को लेकर असहमति और स्पष्ट रणनीति की कमी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

असम के हर परिवार से अप्रील है - अष्टाचार मे एक भी और दिन नही गुजारना।
हिमंता ने असम को लूटा है - यह असम जानता है, देश जानता है।
कल बदलाव का दिन है।
कांग्रेस गठबंधन को वोट दे।

जय असम, जय हिंद।
-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

महान समाज सुधारक व 'सत्य शोधक समाज' के संस्थापक स्वर्गीय ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर भावपूर्ण नमन।
ज्योतिबा फुले जी का पूरा जीवन सबको समान अवसर, सबको शिक्षा, सबको बेहतर जीवन का संदेश देता है।
महिला शिक्षा के लिये उनकी सोच व समर्पण हम सबको सदैव प्रेरित करता रहेगा।
-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

कुशल और कूटनीतिक विदेश मंत्री हैं एस. जयशंकर

समता पाठक/जगत प्रवाह

सुब्रह्मण्यम जयशंकर भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं, जिन्हें एक कुशल राजनयिक, रणनीतिक विचारक और अनुभवी प्रशासक के रूप में जाना जाता है। उनका पूरा नाम सुब्रह्मण्यम जयशंकर है। उनका जन्म 9 जनवरी 1955 को नई दिल्ली में हुआ। उनके पिता के. सुब्रह्मण्यम भारत के एक प्रसिद्ध रणनीतिक विशेषज्ञ थे, जिसका प्रभाव जयशंकर के जीवन और करियर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जयशंकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एम.ए., एम.फिल. और पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उन्हें वैश्विक राजनीति और कूटनीति की गहरी समझ प्रदान की।

साल 1977 में जयशंकर भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुए। अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे यूनाइटेड स्टेट, चीन और में भारत के राजदूत रहे। विशेष रूप से अमेरिका और चीन जैसे शक्तिशाली देशों में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही, जहाँ उन्होंने भारत के हितों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। जयशंकर ने 2015 से 2018 तक भारत के विदेश सचिव के रूप में कार्य किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की विदेश नीति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने कई देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया।

2019 में जयशंकर को भारत सरकार में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट में शामिल हुए। एक पेशेवर राजनयिक से सीधे मंत्री बनने का उनका सफर असाधारण माना जाता है। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की विदेश नीति को अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बनाया। जयशंकर की कूटनीति का मुख्य उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को मजबूत करना है। उन्होंने "पड़ोसी पहले" "एक्ट ईस्ट" और "इंडो-पैसिफिक" जैसी नीतियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, उन्होंने वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति को स्पष्ट और सशक्त तरीके से प्रस्तुत किया है।

वे एक लेखक भी हैं और उन्होंने द इंडिया वे नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने भारत की विदेश नीति और वैश्विक दृष्टिकोण को विस्तार से समझाया है। यह पुस्तक काफी लोकप्रिय हुई और नीति-निर्माताओं तथा छात्रों के बीच चर्चा का विषय बनी। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो जयशंकर का विवाह क्योको जयशंकर से हुआ है, जो जापान मूल की हैं। उनके परिवार में तीन बच्चे हैं। वे एक शांत, अनुशासित और विद्वान व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं। अंततः जयशंकर का जीवन भारतीय कूटनीति की उत्कृष्टता का उदाहरण है। उन्होंने अपने ज्ञान, अनुभव और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से भारत को वैश्विक मंच पर नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपना करियर बनाना चाहते हैं।

शिक्षकों के सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन के पीछे क्या है दोहरा खेल?

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह, नरसिंहपुर। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में निकाली गई रैली और हर ब्लॉक पर विरोध कार्यक्रम प्रदर्शन आयोजन अब जिले में व्यापक चर्चा और गहरे वाद विवाद का केंद्र बन गया है। एक ओर जहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता और वरिष्ठता निर्धारण जैसी मांगों को लेकर शिक्षक सड़कों पर उतरे, वहीं दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की रणनीति, नवीन शिक्षक संवर्ग में चंदा वसूली के खेल और स्कूल ड्यूटी के समय प्रदर्शन बिना छुट्टी लिए स्कूल समय अनुशासन ई अटेंडेंस के अवकाश नियम का खुला उल्लंघन को लेकर आमजन और प्रशासन के बीच गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले भर में इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या यह आंदोलन वास्तव में शिक्षकों के हित में है या इसके पीछे कुछ रसूखदारों की अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकने की तैयारी है।

ड्यूटी समय में रैली: छात्रों की पढ़ाई से खिलवाड़ या शक्ति प्रदर्शन?

हैरानी की बात यह है कि पूरे जिले से बड़ी संख्या में शिक्षक अपने निर्धारित स्कूल समय के दौरान शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर जिला मुख्यालय पहुंचे। इस विरोध कार्यक्रम के लिए शिक्षकों का समय से पूर्व स्कूलों से निकल जाना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है। ग्रामीण अंचलों के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों से शिक्षकों के नदारद रहने के कारण शैक्षणिक कार्य पूरी तरह प्रभावित हुआ। जानकारों का स्पष्ट कहना है कि ड्यूटी टाइम पर स्कूलों में शिक्षण कार्य छोड़कर प्रदर्शन में शामिल होना सीधे तौर पर सिविल सर्विस सेवा संहिता का खुला उल्लंघन है। सवाल यह उठ रहा है कि जो शिक्षक स्वयं अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, वे अपनी मांगों के लिए विद्यार्थियों के भविष्य को दांव पर कैसे लगा सकते हैं?

भारी-भरकम चंदा वसूली का अभियान और सुप्रीम कोर्ट का पेच

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस आंदोलन और कानूनी लड़ाई के नाम पर जिले भर के शिक्षकों और अध्यापकों से 1500 रूपये से लेकर 3000 रूपये तक की बड़ी चंदा वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। सवाल यह खड़ा होता है कि जब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करने का पूर्ण आश्वासन दे रही है, सरकारी प्रक्रिया चल रही है विभाग की ओर से शीघ्र पिटीशन दायर होना है टीईटी का मामला पहले से ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और कई प्रदेश स्तरीय संगठन पहले ही अपनी याचिकाएं दायर कर चुके हैं, तब इस स्थानीय स्तर पर की जा रही भारी-भरकम चंदा वसूली का असली मकसद क्या है? क्या साधारण शिक्षकों की भावनाओं और उनके डर का इस्तेमाल किसी बड़े आर्थिक लाभ या निजी कोष को भरने के लिए किया जा रहा है?

मानवता की मिसाल: सेन समाज के युवाओं की अनोखी जल सेवा

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह, टिमरनी। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां लोग धूप से बचने के लिए घरों में रहना पसंद करते हैं, वहीं टिमरनी का सेन समाज मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। सेन समाज के युवा पिछले करीब 2-3 वर्षों से निरंतर सामाजिक सेवा करते हुए प्रत्येक मंगलवार को टिमरनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ठंडा जल उपलब्ध करा रहे हैं। इस सेवा की खास बात यह है कि युवा केवल स्टेशन पर ही नहीं रुकते, बल्कि ट्रेन की बोगियों तक पहुंचकर यात्रियों को पानी पिलाते हैं। गर्मी के मौसम में जब यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी होती है, तब सेन समाज के ये युवा राहत बनकर सामने आते हैं। हर वर्ष अप्रैल, मई और जून जैसे भीषण गर्मी के महीनों में यह सेवा विशेष रूप से चलाई जाती है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बावजूद सेन समाज के युवाओं का उत्साह कम नहीं होता और वे पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इस पहल से न केवल यात्रियों को राहत मिल रही है, बल्कि अन्य सामाजिक संगठनों के लिए भी यह एक प्रेरणा बन गई है। क्षेत्र में सेन समाज की इस सेवा की सराहना हो रही है और लोग इसे सच्ची मानव सेवा का उदाहरण मान रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आज के समय में इस तरह की निस्वार्थ सेवा समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश देती है। सेन समाज के युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि सेवा और समर्पण से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

आज अगर बाबा साहब होते

रघु ठाकुर
सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक और समाजवादी नेता

डॉ. आम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल पर विशेष

14 अप्रैल डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर का जन्म दिन है। इस अवसर पर वे किस सन् में पैदा हुए या किस सन् में उनकी मृत्यु हुई यही बात महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आज अगर बाबा साहब जिंदा होते तो अपनी मान्यताओं, विचारों व स्थापनाओं की रक्षा के लिये, उन्हें किन-किन शक्तियों से जुझना पड़ता। मैं समझता हूँ कि बाबासाहब को सर्वाधिक निराशा या अंतः संघर्ष उन लोगों से ही करना पड़ता जिनकी तरक्की व समता के लिये उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहते भी थे कि मुझे सबसे ज्यादा शिकायत उन अपने ही लोगों से है, जिन्होंने मेरी बातों को या तो नजरअंदाज किया या फिर मुझे केवल पूजने की प्रतिमा बना दिया।

अक्सर देश या दुनिया में ऐसी धारणा बनी है कि बाबा साहब केवल दलितों के नेता थे या उन्होंने केवल दलित उत्थान के लिये कार्य किया, परन्तु यह आंशिक सत्य हैं। निरूसंदेह बाबा साहब दलितों के उत्थान व उन्हें बराबरी दिलाने के लिये एक सतत संघर्षशील सेना नायक थे परन्तु उन्होंने समूचे समाज को बराबरी, प्रगतिशील व मानवीय समाज बनाने के लिये अपना जीवन लगा दिया। उन्हें केवल दलितों का नेता या मसीहा कहा जाना उन्हें जाति के अंदर सिकोड़ना होगा।

बाबा साहब जिन्हें आमतौर पर संविधान निर्माता या संविधान शिल्पी कहा जाता है, अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये संविधान की सीमाओं को वह बेहतर जानते थे। इसीलिये उन्होंने संविधान पारित होने के तत्काल बाद विधि मंत्री के नाते अपने प्रथम साक्षात्कार में कहा था कि आज हम अंतर्विरोध के एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें राजनैतिक समानता तो होगी यानी एक व्यक्ति- एक वोट परन्तु आर्थिक व सामाजिक समानता नहीं होगी। बाबा साहब ने संविधान की जिन सीमाओं को उसके पारित होने के कुछ ही दिनों बाद पहचाना था, आज देश उन संवैधानिक समस्याओं से रुबरु हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से देश की सर्वोच्च न्यायपालिका व विधायिका तथा सत्ता के टकराव के जो मामले सामने आ रहे है, वे इसी का घोतक है। संविधान का मूल खंड भी अपने लक्ष्यों में लगभग असफल जैसा किया जा रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है।

बाबा साहब यह जानते थे कि परिवर्तनशीलता का गुण विकास के लिये जरुरी है। उन्होंने इमर्सन को उद्धत करते हुये कहा था कि स्थिरता गधे का गुण उन्होंने अपने विचारों में भी, समय-समय पर बड़े परिवर्तन किये जो उनके अनुभवों पर आधारित थे।

बाबा साहब में भारतीयता गहरे तक थी। उनके दो ही लक्ष्य थे एक भारत महान बने और दूसरा सामाजिक अन्याय समाप्त हो। जो लोग उन पर यह आरोप करते है कि वे भारत की आजादी के पक्ष में नही थे, वे उनका गलत विश्लेषण करते है। वे भारत को आजाद देखना चाहते थे परन्तु उसके पूर्व या साथ में अपनी दलित कौम की भी आजादी चाहते थे। उनके मन में यह संशय अवश्य रहता था जो कि स्वाभाविक भी था कि कहीं ऐसा न हो कि देश तो आजाद हो जाये परन्तु देश की अनुसूचित जातियाँ,उच्च जातियों की गुलाम बनी रह जायें। इसीलिये उन्होंने 1938 में बंबई विधानसभा में कहा था कि श्मुझे अकसर गलत समझा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिये कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ लेकिन मैं इस देश के लोगों को यह बात भी साफ-साफ बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक और निष्ठा है जिसके लिये मैं प्रतिबद्ध हूँ। यह निष्ठा है अस्पृश्य समुदाय के प्रति जिसमें मैंने जन्म लिया है और मैं इस सदन में पूरे जोर-शोर से कहना चाहता हूँ कि जब कभी देश हित और अस्पृश्यों के हित के बीच टकराव होगा तो मैं अस्पृश्यों के हितों को तरजीह दूँगा। पर अगर मेरे अपने हित और देश हित के साथ टकराव होगा तो मैं देश हित को तरजीह दूँगा। बाबा साहब के मन में भारतीय राष्ट्रवाद बहुत स्पष्ट था। वे भाषावार प्रांतों के विरोध में थे क्योंकि वे महसूस करते थे कि भाषावार प्रांत आगे जाकर किसी दिन क्षेत्रवाद व देश के विभाजन के कारण बन सक्ते हैं। उनके ही शब्दों में भाषावार प्रांतो में छोटे-छोटे समुदायों अर्थात अल्पसख्यक जातियों का क्या भविष्य है? क्या ये विधायिका में चुने जाने की आशा रखें? क्या उन्हें राज्य सेवा में कोई पद मिलने की आशा है? भाषावार राज्यों के गठन के बारे में जो चेतावनी बाबा साहब ने 1938 में दी थी। वह आज स्पष्ट नजर आती है। भाषावाद राज्यों के गठन से भाषावाद की कट्टरता व क्षेत्रीयता बढ़ी है तथा राष्ट्रीय एकता कमजोर हुई है। शिवसेना पर भी असर हुआ है, कहते थे कि श्आमची मुंबई मराठी मुंबईय या अन्य प्रांतों के निवासियों को हेय दृष्टि से भैया माणुस्य कहकर अपमानित करते हैं या फिर अन्य राज्यों के निवासियों के साथ दंगे फसाद कर उन्हें भगाने का प्रयास करते है तो बाबा साहब की 88 वर्ष पूर्व दी गई चेतावनी याद आ जाती है। आज ये राष्ट्रीय हितों के बजाय क्षेत्रीय हितों के पर्याय बन रहे है। आजादी के 78 वर्ष के बाद भी कर्नाटक व तमिलनाडू के बीच कावेरी जल विवाद नहीं सुलझ पाया। पंजाब तथा हरियाणा के बीच सतलज, यमुना, जल विवाद नहीं निपट पाया। क्षेत्रीय भाषा प्रेम या मातृभाषा, प्रेम, भाषावाद में संकुचित हो रहा है जिसके परिणाम स्वरुप राष्ट्रभाषा का फैलाव भी रुक गया है। आज तमिलनाडू, पंजाब, बंगाल, केरल, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में क्रमशः तमिल, गुरमुखी, बंगाली, मलयाली, तेलगू, कन्नड़ या उड़िया के साथ अंग्रेजी होती है न कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी हिन्दी के विरोध में क्षेत्रीय राजनैतिक शक्तियाँ दंगे कराने को तत्पर रहती है परन्तु अंग्रेजी पर उन्हें कोई गुस्सा नहीं आता। अगर राज्य केवल एक ही भाषा व परंपराओं के लोगों का बंद किला बन जायेगा तो भारत राष्ट्र कहाँ व कब तक टिकेगा, क्या मजबूत बनोगे? यह जो प्रश्न बाबा साहब ने खड़ा किया था अब आज और ज्यादा प्रांसगिक हो गया है।

बाबा साहब ने दूसरा शत्रु पुंजीवाद को घोषित किया था। वे पूंजीवाद मिटाना चाहते थे, न कि दलित पूंजीवाद चाहते थे। पर कुछ लोग जो बाबा साहब का नाम लेते हैं पुंजीवाद या विषमतरू को नहीं मिटाना चाहते वरन अपनी जाति के पुँजीवाद बनाना चाहते हैं। आज विषमता इतनी भारी है कि ऑक्सफेम के अनुसार देश के 166 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जितनी देश की 70 करोड़ आबादी के पास। आज देश में 200-300 (खरबपति) बड़ी जातियों के लोग है जो देश की 100 करोड़ की आबादी का शोषण कर पूंजी के मलिक बने है। कल यदि इनमें से 5-10 दलित के घर में जन्मे,पूंजीपति बन जाये तो क्या देश के 20 करोड़ दलितों का उत्थान हो जायेगा? औसतन 53 लाख लोगों की कीमत पर एक अरबपति बनता हैं। वह चाहे सवर्ण बने या शुद्र। अगर 53 लाख शुद्रों की लाश पर एक दलित पूंजीपति बने तो क्या इससे शूद्रों का कोई भला होगा? यह व्यवस्था बाबा साहब की अभीष्ट नहीं थी। वे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक समानता चाहते थे। वे समाजवाद चाहते थे जो सभी के लिये हो। बाबा साहब मूल उद्योगों को सरकारी रखना चाहते थे तथा निजी पुंजी को समता के बंधनों में कैद करना चाहते थे। क्या बाबा साहब के इन संदेशों को देश समझेगा, मानेगा और अमल में लायेगा? मैं सोचता हूँ कि अगर आज बाबा साहब होते तो, 1940-50 के दशक में तो वे अपनों से निराश थे पर 21वीं सदी के आरम्भ में अपनों व परायों के सामने समता व समाजवाद के संघर्ष की महाभारत में अर्जुन बनकर लड़ रहे होते।

असम, केरल और पुडुचेरी में बंपर मतदान किस पर भारी

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

देश के दो राज्य केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बंपर मतदान ने न केवल राजनीतिक दलों को बल्कि पूर्वानुमान लगाने वाले टीवी चैनलों को भी संशय में डाल दिया है। हालांकि जिस तरह का माहौल है, उससे तय है कि असम में भाजपा को एक बार फिर घुसपैठियों का मुद्दा तारणहार बनने जा रहा है, वहीं केरल में सत्तारूढ़ दल सीपीआई के नेतृत्व वाला एलडीएफ गठबंधन सकते में है। केरल में हुई 78.01 प्रतिशत मतदान ने सभी को चौंका दिया है। असम में जहां 85.38 प्रतिशत मतदान हुआ है, वहीं पुडुचेरी में 89.81 मतदान हुआ है। 2021 की तुलना में केरल में 4.11, असम में 2.89 और पुडुचेरी में 11.91 प्रतिशत मतदान बढ़ा है। इस कारण केरल में संकेत मिलने लगे है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के विरुद्ध एंटी इनकंबेंसी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। विजयन पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री हैं। इस संकेत से कांग्रेस नीत यूडीएफ प्रसन्न है। इस बार सीपीआईएम के खिलाफ मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर मतदान के लिए बाहर आया है। साफ है, इन राज्य-विधानसभाओं में मतदान के बढ़े प्रतिषत ने सारे मापदण्ड ध्वस्त कर दिए हैं।

इन तीनों राज्यों में कुल 296 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। इन राज्यों में 5.31 करोड़ मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर चुनावी यज्ञ में अपनी आहुती देकर 1849 प्रत्याषियों का भाग्य ईवीएम में बंद कर दिया। असम में 2.50 करोड़ मतदाता और 722 उम्मीदवार हैं। यहां अभी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा संभाले हुए हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस से है। सरमा ने जिस तरह से घुसपैठियों के विरुद्ध आक्रामक तेवर अपनाए हुए है, उनसे एक बार फिर सरमा की वापसी तय लग रही है। क्योंकि बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या घुसपैठियों ने सीमावर्ती जिलों में न केवल स्थानीय मूल निवासियों के संसाधनों को कब्जा लिया है, बल्कि असम का जनसांख्यकीय घनत्व बिगाड़ा हुआ है। धर्मांतरण के साथ ये घुसपैठिए देश विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त पाए गए है। स्थानीय जनजातीय समुदायों से इनका सांप्रदायिक संघर्श भी निरंतर सामने आता रहा है। अतएव असम में घुसपैठिए बड़ा मुद्दा बनकर भाजपा को लाभ पहुंचाने की स्थिति में है। यदि सरमा फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो असम में घुसपैठियों की समस्या लगभग समाप्त हो जाने की उम्मीद बढ़ जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी घुसपैठ को अपनी सभाओं में बड़ा मुद्दा बनाकर पेष करते रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति इस राज्य में इसलिए खराब होती रही है, क्योंकि वह असम के सीमावर्ती जिलों और बराक घाटी समेत पूरे असम में अवैध प्रवासियों को षरण देने की पैरवी करती रही है। इसलिए कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध किया और एसआईआर का भी विरोध किया। क्योंकि अपने मतदाता बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने घुसपैठियों को राशन, आधार कार्ड और मतदाता पहचान-पत्र बनवाने का काम किया हुआ है। असम में एसआईआर के बाद 02 लाख 43 हजार मतदाता कम हुए हैं। जबकि अभी भी ये घुसपैठिए बड़ी संख्या में मतदाता बने हुए हैं।

केरल में पिनाराई विजयन को एंटी इनकंबेंसी के साथ क्षेत्रीय नेताओं की कमी का भी सामना करना पड़ा है। दरअसल विजयन ने सेकंड लाइन के नेतृत्व को पनपने ही नहीं दिया है। इस कारण कई प्रभावशाली नेता अपने भविष्य की चिंता करते हुए वैचारिकता की परवाह किए बिना भाजपा और कांग्रेस की शरण में चले गए। ऐसे में इन नेताओं ने पार्टी कैडर की भी चिंता नहीं की। सबरीमाला मंदिर के धार्मिक विवाद ने भी विजयन को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इस मंदिर में गहनों की चोरी का मुद्दा भी विजयन के खिलाफ गया है। चूंकि सबरीमाला मंदिर का विवाद महिलाओं से जुड़ा है, इसलिए केरल में महिलाओं ने मतदान में जबरदस्त उत्साह दिखाया है। यहां महिला मतदाताओं की संख्या 1.39 करोड़ हैं, जो पुरुश मतदाताओं की तुलना में करीब 7 लाख अधिक है।

बावजूद मत प्रतिशत का सबसे अहम, सुखद व सकारात्मक पहलू है कि यह अनिवार्य मतदान की जरूरत की पूर्ति कर रहा है। हालांकि फिलहाल हमारे देश में अनिवार्य मतदान की संवैधानिक बाध्यता नहीं है। मेरी सोच के मुताबिक ज्यादा मतदान की जो बड़ी खूबी है, वह है कि अब अल्पसंख्यक व जातीय समूहों को वोट बैंक की लाचारगी से छुटकारा मिल रहा है। इससे कालांतर में राजनीतिक दलों को भी तुष्टिकरण की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि जब मतदान प्रतिशत 75 से 85 होने लगता हैं, तो किसी धर्म, जाति, भाशा या क्षेत्र विशेष से जुड़े मतदाताओं की अहमियत कम हो जाती है। नतीजतन उनका संख्याबल जीत या हार की गारंटी नहीं रह जाता। लिहाजा सांप्रदायिक व जातीय आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नगण्य हो जाती है। कालांतर में यह स्थिति मतदाता को धन व शराब के लालच से भी मुक्त कर देगी। क्योंकि कोई प्रत्याषी छोटे मतदाता समूहों को तो लालच का चुग्गा डालकर बरगला सकता है, लेकिन संख्यात्मक दृष्टि से बड़े समूहों को लुभाना मुश्किल होगा? बावजूद इन चुनावों में जातीय और अल्पसंख्यक राजनीति सभी दलों की कार्यशैली में खुले रूप में दिखाई दी है। साफ है, जातीय कुचक्र का धरातल नीचे से नहीं, बल्कि ऊपर से करने के उपाय किए जा रहे हैं।

पर्यावरण के कर्जदार हैं हम, मालिक नहीं

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

हमारी समृद्धि, हमारी रक्षा, हमारी पहचान, यह सब कुछ इस देहाती, जंगली और अनंत सृष्टि में निहित है, जो हम खुद ही खोते जा रहे हैं। हम प्रकृति की गोद में पलकर बड़े हुए हैं। हमारे पुरखों ने मिट्टी में हाथ डालकर अनाज उगाया, नदियों में टिका कर जीवन बसर किया, जंगलों की हरी-भरी चादर में ठहर कर खुद को पाया। यही कारण है कि मनुष्य की जड़ें पर्यावरण से इतनी गहरी हैं कि हमारा अस्तित्व उसी पर टिका है। विगत दशकों में हमने अवैज्ञानिक अतिक्रमण, बे रोक टोक वृक्ष वनों की कटाई, नदियों की निर्मम धमनियों में कूड़ा-करकट बहाया। परिणामस्वरूप आज हमारे जंगल जल रहे हैं, मौसम अप्रत्याशित रूप से पागल हो गया है और जीवन-दायिनी नदियाँ, जो कभी हमारी पीढ़ियों को प्यास से बचाती थीं, अब जहरीले विषाक्त पदार्थों की धारा बहे रही हैं। देश भर में प्रति वर्ष लाखों हेक्टेयर वन कटते हैं। हिमालय से अरुणाचल तक, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव ने सूखाग्रस्त प्रदेशों में भीषण सूखे और बरसात की अनियमितता ला दी है। कभी जो चक्रवाती तूफान बेहद दुर्लभ हुआ करते थे, आज वे बार-बार दस्तक दे रहे हैं। शहरों की आकाश-सीमा अब जहरीली गैसों से धुंधली हो चुकी है। प्रदूषण के काले बादल गहरे होते जा रहे हैं, और हमारी सांसें घुटने लगती हैं। इन संकेतों ने एक चेतावनी की जन्म दी है कि "पर्यावरण हमसे नहीं"। यह हमारे स्वामित्व का विषय नहीं है।

हमारे सरोकार सीमित होते जा रहे हैं- विकास का मतलब केवल इमारतों की ऊँचाइयाँ, सड़कों का विस्तार, उद्योगों की चमक नहीं है। उद्योगों ने जीवन को सुविधाजनक बनाया, लेकिन उसी उद्योग ने वातावरण को विषैला कर दिया। हम भूल गए कि "ऊँचाइयाँ" हासिल करने का अर्थ यह नहीं कि हम धरती को अपने पांवों के नीचे कुचल दें। विकास तब सार्थक है, जब यह प्राकृतिक संतुलन को भंग न करे, बल्कि उसमें सौहार्द और सहजीवन की भावना भर दे। हमारे साथ ही अनेकों जीवों का अस्तित्व उस पर्यावरण से बंधा है जिसे हम अपमानित कर रहे हैं। तेंदुए से लेकर तितलियों, पत्थर की खदानों से पत्तों पर झूलते भौंरे तक सभी के जीवन चक्र को हम कठोरता से तोड़ रहे हैं। अवैध शिकार, आवास नष्ट होने से अनेक प्रजातियाँ लुप्तप्राय हो चुकी हैं। कीट पतंग फसलों की रक्षा के लिए प्रयोग हो रहे कीटनाशकों ने परागण करने वाले कीटों को अक्षम कर दिया, जिससे खाद्य शृंखला बाधित हो रही है। नदियों में रसायनों का मिलना, प्लास्टिक कचरा आदि मछलियों और अन्य जलचर प्रजातियाँ दम तोड़ रही हैं। हमारी लापरवाही ने न केवल एक-दो प्रजातियों को समाप्त किया, बल्कि समूचे पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर किया, जिससे अन्न चक्र, जल चक्र और कार्बन चक्र पर संकट मंडरा रहा है।

वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भोजन में मिलावटी पदार्थों ने हमारी सेहत पर भी संकट की घंटियाँ बजा दी हैं। दिन में दर्जनों बार धुंधली आकाश गंगाएँ हमें याद दिलाती हैं कि स्वस्थ जीवन के चारों ओर एक जहरीला घेरे जैसा छा चुका है।अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं।दमा, हैजा, पेचिश आदि रोगों का प्रसार बढ़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य के विनाश ने हमें आंतरिक रूप से भी अशांत कर दिया है। अध्ययन बताते हैं कि हरियाली की कमी से डिप्रेशन और तनाव में बढ़ौतरी होती है।

सरकारों ने कई योजनाएं चलाई है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, पीएम-कुसुम, नेशनल पार्क्स का विस्तार। फिर भी जमीनी हकीकत शर्मनाक है। नीति-निर्माता और उद्योगपति मुनाफे के चक्कर में ईंधन-दहन, खनन, औद्योगिक कचरे का प्रबंधन ढंग से नहीं कर पा रहे। जब तक नीतिगत गंभीरता नहीं आएगी, तब तक "हम पर्यावरण से हैं" का उद्घोष पेट भरने वाला वाक्य ही रहेगा। हमें चाहिए पर्यावरण अपराधों पर त्वरित और व्यापक दंडात्मक प्रावधान, इकाइयों के लिए जीरो-लिकेज मानक, ईटीपी का अनिवार्य निर्माण, तेल की जगह सौर, पवन, बायोमास को प्राथमिकता। कटे हुए वन पुनःरोपण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी। नीति तभी प्रभावी होगी, जब फाइलों में कैद शाब्दिक प्रतिवेदन नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाले बदलाव हों। जो जिम्मेदारी सरकार पर है, वह नागरिकों के सहयोग के बिना अधूरी है। हमें अपनी दैनिक आदतों में सुधार लाना होगा जैसे साइकिल, पैदल, सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग , पुनः प्रयोगी बैग कांच या स्टील की बोतलों का उपयोग। इन छोटे-छोटे कदमों से एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में पर्यावरणीय सुधार की लहर दौड़ सकती है। हमारे बच्चों के लिए यह संदेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वे नहीं जानेंगे कि कभी आकाश नीला था, नदियाँ निर्मल थीं और जंगल गूंजते थे। यदि हमने अभी सुधार नहीं किया, तो हमारे प्रयास खोखले साबित होंगे।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि पर्यावरण हमारा साथी है। इसका अपमान स्व-अपमान के समान है। हमें इसकी रक्षा करनी है, पोषण करना है, और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ, सुंदर और संतुलित विश्व सौंपना है। समय निकल चुका है। अब सिर्फ चिंतन-मनन नहीं, कार्रवाई चाहिए। हम स्वयं को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी सभ्यता को, और अपनी धरती को बचाने के लिए खड़े हों। आज नहीं तो कभी नहीं। पर्यावरण का सम्मान करें, क्योंकि वह हमारा पालनहार है, हम उसके सेवक।

री-स्किलिंग: 'आउटडेटेड' नहीं, 'अपडेटेड' कहलाने की जिद बनें

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

कल्पना कीजिए, अगर आपकी आज की सबसे बड़ी ताकत कल आपकी सफलता की सीढ़ी ही न बन पाए तो? आज का विश्व इसी मोड़ पर खड़ा है- जहाँ बदलाव की रफ्तार केवल 'तेज' नहीं, बल्कि 'विस्फोटक' है। आज का युवा वर्षों की कड़ी मेहनत से प्रतियोगी परीक्षाएं पास करता है और एक डिग्री हासिल करता है, लेकिन जब तक वह नौकरी या व्यापार की दहलीज पर कदम रखता है, उसकी वह डिग्री 'आउटडेटेड' होने की कगार पर होती है। बदलते वक्त के साथ खुद को 'अपडेट' करने की जिद ही आपको रेस में बनाए रखती है। यहाँ डिग्री की एक्सपायरी डेट हो सकती है, लेकिन आपके भीतर सीखने का जज्बा ही वह महामंत्र है जिसे हम 'री-स्किलिंग' कहते हैं। इतिहास गवाह है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, लेकिन आज परिवर्तन की गति अभूतपूर्व है। कल की विशेषज्ञता आज की सामान्य जानकारी बन चुकी है। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, बल्कि यह है कि क्या आप आज कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? 'री-स्किलिंग' अब केवल कॉरपोरेट जगत का कोई भारी-भरकम शब्द नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए 'सर्वाइवल किट' है जो इस डिजिटल युग में अपनी प्रासंगिक पहचान बनाए रखना चाहता है।

मैंने अपनी युवावस्था, पुलिस सेवा के चुनौतीपूर्ण वर्षों, प्रशासनिक समन्वय की जटिलताओं और अपने सामाजिक जीवन के लंबे सफर में एक बात बहुत गहराई से सीखी है- वक्त के साथ खुद को अपडेट न करना ही सबसे बड़ा जोखिम है। अगर आप समय की चाल के साथ कदमताल करना चाहते हैं, तो केवल पुरानी उपलब्धियों के सहारे नहीं बैठ सकते। यहाँ डिग्री की एक्सपायरी डेट हो सकती है, लेकिन सीखने की आदत अमर है। और इसी बदलते वक्त का महामंत्र है- री-स्किलिंग।

विद्यार्थी: बस्ते के बोझ से हुनर की उड़ान तक

मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिए कि मार्कशीट केवल आपकी याददाश्त का प्रमाण पत्र हो सकती है, आपकी योग्यता का नहीं। आज की इस सुनहरी सुबह आपको यह समझना होगा कि केवल कक्षा की चारदीवारी में बैठकर भविष्य नहीं गढ़ा जा सकता। आज का दौर 'मल्टी-टास्किंग' और 'एक्टिविटी' का है। अगर आप केवल किताबी कीड़ा बने रहेंगे, तो दुनिया के इस विशाल मंच पर पीछे छूट जाएंगे। खेल हो, कला हो या कोई तकनीकी हुनर- अपनी पढ़ाई के समानांतर एक ऐसी स्किल विकसित कीजिए जो संकट के समय आपकी पहचान बन सके। आज कई वैश्विक रिपोर्ट्स संकेत दे रही हैं कि आने वाले पाँच वर्षों में लगभग 40% स्किल्स बदल जाएंगी। यानी जो आज सीखा है, वह कल पर्याप्त नहीं होगा। डिग्री आपको इंटरव्यू तक ले जा सकती है, लेकिन आपकी स्किल्स ही आपको सफलता की कुर्सी पर बैठाती हैं।

युवा: कॉलेज की देहरी और हुनर की जरूरत

यह चुनौती केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है। कॉलेज से निकलने वाले युवाओं के लिए आज की सच्चाई कड़वी जरूर है, लेकिन जरूरी भी। 2026 का बाजार आपसे यह नहीं पूछता कि आपने क्या पढ़ा है, वह पूछता है कि आप क्या 'कर' सकते हैं। केवल कॉलेज की पढ़ाई आपको एक ढांचा दे सकती है, लेकिन उस ढांचे में प्राण आपकी स्किल्स भरेंगी। डिजिटल साक्षरता से लेकर संवाद कौशल तक, खुद को हर दिन अपडेट करना ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस दौर में, जो मशीन नहीं कर सकती वही आपकी असली ताकत है। अपनी स्किल को अपडेट करते रहिए, वरना समय आपको 'आउटडेटेड' की श्रेणी में डाल देगा।

नौकरीपेशा: पद का नहीं, व्यक्तित्व का प्रमोशन

दफ्तरों में अक्सर लोग सालों-साल एक ही ढर्रे पर काम करते हुए बोरियत और असुरक्षा का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए, प्रमोशन का मतलब केवल केबिन का बड़ा होना या सैलरी का बढ़ना नहीं है। असली प्रमोशन तब होता है जब आपकी कार्यक्षमता और आपके हुनर में इजाफा होता है।

क्या आप आज भी वही टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपने पाँच साल पहले सीखे थे? अगर हाँ, तो आप जोखिम में हैं। दफ्तर में केवल 'कुर्सी' मत संभालिए, अपने भीतर के 'सीखने वाले' को जीवित रखिए। री-स्किलिंग आपको भीड़ से अलग करती है और आपको एक ऐसा 'एसेट' बनाती है जिसे कोई खोना नहीं चाहता।

व्यापारी: पारंपरिक नींव पर आधुनिक निर्माण

यह चुनौती व्यापार जगत के लिए भी उतनी ही बड़ी है। आज ग्राहक बदल रहा है, तकनीक बदल रही है और सप्लाई चेन के मायने बदल रहे हैं। एक ही ढर्रे पर व्यापार करने का दौर अब समाप्त हो चुका है। अगर आप अपने व्यापार के तरीकों को 'री-स्किल' नहीं करेंगे, तो प्रतिस्पर्धा की आंधी आपको पीछे छोड़ देगी। वैश्विक बाजार की नब्ज पहचानिए और खुद को आधुनिक माध्यमों से जोड़िए। व्यापार केवल लेन-देन नहीं, बल्कि बदलते वक्त के साथ तालमेल बिठाने की कला है।

गृहिणियां: घर की धुरी और नई संभावनाएं

यह बदलाव समाज के हर वर्ग के लिए है। एक होममेकर पूरे परिवार की रीढ़ होती है। आज जब परिवार की जरूरतें और बच्चों की परवरिश के तरीके बदल रहे हैं, तो गृहिणियों के लिए भी री-स्किलिंग उतनी ही आवश्यक है। बजट प्रबंधन से लेकर बच्चों की मनोवैज्ञानिक समझ और डिजिटल दुनिया से जुड़ाव तक- जब एक महिला खुद को अपडेट करती है, तो पूरा परिवार अपग्रेड हो जाता है। री-स्किलिंग आपको केवल कुशल नहीं बनाती, यह आपको आत्मविश्वास से भी भर देती है।

आस्था का दिव्य महाकुंभ
पूरा विश्व देखेगा उज्जैन का वैभव

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

30 करोड़ श्रद्धालुओं का स्वागत
उज्जैन नगरी का हो रहा अभूतपूर्व कायाकल्प

सुगम आवागमन ₹ 13,536 करोड़ से 581 कि.मी. मार्गों का चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य प्रगतिरत

पुल निर्माण ₹440 करोड़ के निर्माण से यातायात का बेहतर प्रबंधन

शुद्ध जल क्षिप्रा के लिये ₹ 919 करोड़ लागत की कान्ह क्लोज्ड डक्ट परियोजना एवं शहर में पेयजल आपूर्ति हेतु ₹1113 करोड़ के कार्य जारी

घाट निर्माण लगभग 29 कि.मी. घाटों का निर्माण जारी

ज़ीरो वेस्ट इवेंट जन भागीदारी से ज़ीरो वेस्ट इवेंट बनाने की पहल

मंदिरों का जीर्णोद्धार
सभी पौराणिक मंदिर जैसे हरसिद्धि, गढ़कालिका का विकास

आधुनिक तकनीक से प्रबंधन
भीड़ नियंत्रण से लेकर ट्रांसपोर्ट और कंट्रोल रूम तक एआई का उपयोग

कनेक्टिविटी विश्वस्तरीय उज्जैन हवाई अड्डा और सदावल में 4 हेलीपैड का निर्माण कार्य जारी

उज्जैन बनेगा मेडिकल हब
₹ 592.30 करोड़ लागत से मेडिसिटी एवं मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन

R.O. No. : D19005/26

सिंहस्थ 2028

"सिंहस्थ महापर्व 2028 करोड़ों भक्तों को सरल, सुलभ और नवीनतम सुविधाओं से युक्त विश्व-स्तरीय कुंभ का अनुभव प्रदान करना हमारा संकल्प है।"

- डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)